शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 5609 /सत्तर–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा LMS(Learing Managemaent System) विकसित जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

कोविड–19 जैसी महामारी के अनुभव से प्रतीत होता है कि भविष्य में भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु संस्थानों को पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के साथ–साथ अन्य गुणवत्तापूर्ण वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली को भी तैयार करने की आवश्यकता है। तद्सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भी प्रौद्योगिकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केन्द्रित किये जाने हेतु इंगित किया गया है। संस्थानों द्वारा ऑनलाअन/डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करने का अध्ययन करते हुए उससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होगा। साथ ही, सभी विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म को और सशक्त करना होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक प्रभावी Learning Management System (LMS) बनाया जाय एवं सरल एवं आसानी से प्रयोग होने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए महत्व के दृष्टिगत ऑनलाइन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों की क्षमताओं में अभिवृद्वि के लिये निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(क) – उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का अधिकाधिक उपयोगः– दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया गया। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ई–कन्टेन्ट उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में अधिक मात्रा में ई–कन्टेन्ट अपलोड किए जाने के लिये माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को ''विद्यादान माह'' घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त लाइब्रेरी पोर्टल पर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा 68,000 से भी अधिक ई–कन्टेन्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अपलोड किए गए हैं। इस माध्यम से हर

छात्र को गुणवत्तायुक्त ई–पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो गयी है। यह लाइब्रेरी ज्ञान का एक अनूठा संग्रहण है। इसका अधिकाधिक उपयोग छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिये।

(ख) ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययनः– ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों का उपकरणों की आदत, ई–कन्टेन्ट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया जाय।

(ग) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरः– भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कई प्लेटफार्मो और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाए।

(घ) ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण :– विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिये शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संचरित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित व्यवस्था प्रदान करने के लिये उपयुक्त मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाये। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिये दो–तरफा वीडियो और दो–तरफा–ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।

(ड) सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार :– कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी के निर्माण सहित कंटेन्ट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाये, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिये उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिये एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिये मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण भी बनाये जाये। छात्रों को ई–सामग्री का प्रसार करने के लिये एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाये।

(च) डिजिटल अंतर को कम करना :– इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिये बड़े पैमाने पर किया जाये। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराया जाये। स्थानीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस पर विशेष बल दिया जाये कि जहां तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।

(छ) वर्चुअल लैब्स :– वर्चुअल लैब्स बनाने के लिये मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाये ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग–आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाये और उन्हें विकसित किया जाये।

(ज) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण और प्रोत्साहन :– शिक्षकों को शिक्षार्थी–केन्द्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाए और यह भी बताया जाए कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके

उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई–सामग्री के साथ–साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिये शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाए।

भवदीय,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–5609 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः

1– समस्त कुलपति राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को मार्गदर्शन देते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.